

सम्पादकीय

अंततः आयकर कटौती

लंबे असरें से बढ़ती कीमतों, स्थिर वेतन और करों के बोझ से मध्यम वर्ग वित्तीय दबाव में था। केंद्रीय बजट 2025 में मोदी सरकार ने आयकर छूट सीमा बढ़ाकर व कर दरों में कमी से राहत देने की कोशिश की है। किंतु-परंतु न हो तो अब बारह लाख तक की आय वाले व्यक्ति को कोई कर नहीं देना होगा। धारणा है कि इससे लोगों की आय बढ़ने से उपभोक्ता खर्च में बढ़ जाएगा। खपत में बढ़ से मांग बढ़ेगी जो कालांतर उद्योगों-अर्थव्यवस्था को गति देगी। निस्संदेह आयकर व्यवस्था का सरलीकरण स्वागत योग्य कदम है। वरिष्ठ नागरिकों की व्याज आय पर कटौती की सीमा को दुगनी करके एक लाख रुपये सालाना करने से उन्हें लाभ मिलेगा। इसी तरह किराये की आय पर निर्भर सेवानिवृत्त लोगों को बढ़ी हुई टीडीएस सीमा का लाभ होगा, जिसे अब बढ़ाकर छह लाख सालाना कर दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर ईपीएफपीपीएफ बीमा और होम लोन पर प्रमुख कटौतियों का लाभ हटाने से आम आदमी की वास्तविक बचत खत्म हो सकती है। जिससे दीर्घकालीन बचत में गिरावट संभवित है। नई व्यवस्था पीएफ और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश को होत्साहित करती है। यह स्थिति उनकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को कमज़ोर कर सकती है। कर राहत के साथ जरूरी है कि मध्यम वर्ग की आय में बढ़िया हो और मुद्रास्पैदि पर नियंत्रण किया जाए। निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त लोगों की सामाजिक सुरक्षा के बारे में भी सोचना जरूरी है। लेकिन आयकर राहत से मध्यम वर्ग की बचत-खपत बढ़ने से क्या वास्तव में आर्थिकी को गति मिल सकेगी? एक अनुमान के अनुसार भारत में आबादी का चालीस प्रतिशत मध्यम वर्ग के दायरे में आता है। दरअसल, भारतीय अर्थव्यवस्था मांग की कमी से जूझ रही है। मध्य वर्ग ही वस्तुओं और सेवाओं का बड़ा उपभोक्ता वर्ग है। उसकी क्रय शक्ति कम होने व बचत नहीं होने से उसकी खरीद क्षमता बाधित हुई है। मांग कम होने से उत्पादन में गिरावट आई है और नया निवेश प्रभावित हो रहा है। यही वजह है कि बीते वर्ष में विकास दर पिछले चार सालों में सबसे कम 6.4 रही है कि जिसके आर्थिक सर्वे में इस साल 6.8 तक रहने का अनुमान है। जो विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। सरकार का मानना है कि आयकर में कटौती से बचत और खपत को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल, मध्यम वर्ग उपभोक्ता, कर्मचारी और सहायक सेवा करने वाले लोगों का नियोक्ता होता है। सरकार मानती है कि इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। वहीं कुछ अर्थस्थितियों का मानना है कि देश में अप्रत्यक्ष करों में कमी से मांग को ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। अप्रत्यक्ष कर मध्यमवर्ग के बजाय गरीब लोगों को भी देना पड़ता है। दरअसल, हमारी एक सौ चालीस करोड़ की आबादी में नौ करोड़ लोग आयकर रिटन भरते हैं और साढ़े तीन करोड़ लोग आयकर देते हैं। इनको राहत देने से सीमित वर्ग की क्रय शक्ति ही बढ़ेगी। कुछ लोग इसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से उठाया गया कदम बताते हैं क्योंकि वहीं बड़ी संख्या में आयकर दाता सरकारी कर्मचारी रहते हैं।

सता में बने रहने का चुनावी बजट

दिल्ली में चुनाव प्रचार के अखिरी सप्ताह में बाजी पलटने के संकेतबजट 2025-26 के दो कामन्मांग को बढ़ावा देना और अधिक नौकरियां पैदा करना एनडीए सरकार ने 1 फरवरी को अपना पूर्णकालिक बजट पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के इस पहले पूर्ण बजट में सत्ता पर किसी भी तरह बने रहने की भाजपा की लालसा साफ तौर पर नजर शून्य पर वह कभी नहीं पहुंची। यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में वह सबसे कम केवल दो सीटों पर रह गई और

मिलने जुलने वाला नेता है। सच तो यह है कि कई बार यह कहा जाता है कि देश के लोग राहुल को नहीं पहचान पा रहे। सही सोचती। बस उसे नफरती बातों से ही खुशी मिलती रहती है। कोई भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए जनता का नशा टूटा नहीं है। हरियाणा जो कि वह ज़रूर जाती तो क्या महाराष्ट्र के लोगों का ग्रेस हरियाणा जीत जाएगा।

माहात्मा गांधी के बारे में इनका विवरण है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को अफ्रीका प्रान्त के एक शहर अपेप्रेटर्स बोर्डर्स में हुआ। उनकी परिवार का नाम ठाकरे था। उनकी माता पाता का नाम राधाकृष्णन था। उनकी बड़ी बहन दिल्ली चुनाव के बाद राहुल को पूरा समय पार्टी संगठन के पुनर्निर्माण में लगाना चाहिए। जाने कितने साल हो गए कुछ लोग पदों पर बैठे हुए हैं। उनका कमरा बदल दिया जाता है। जिम्मेदारी बदल दी जाती है। मगर पद बरकरार रहता है। कुर्सियों से चिपके हैं। इनकी बीच उपयोगिता है? इनके बदले और लोगों को मौका देना चाहिए। साल 2025 कांग्रेस ने संगठन का साल घोषित किया है। अगर सही मायनों में हो गया तो पार्टी की तकदीर बदल सकती है।

दिल्ली के नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस अकेली चलेगी या फिर अनिर्णय में फंसी रहेगी



बिहार में 2010 के विधानसभा चुनाव में वह सबसे कम केवल 4 सीटों पर रह गई थी। तीनों जगह दिल्ली, बिहार, यूपी इस बात में समानता है कि कांग्रेस कहीं भी एक निर्णय नहीं ले सकी। कभी साथ में कभी अकेले चुनाव लड़ती रही। यूपी में 1989 के बाद से वह सत्ता से बाहर है। और बिहार 1990 के बाद से। मतलब करीब 35-36 साल से। दिल्ली में भी 11 साल हो गए। मगर अब दिल्ली में कांग्रेस जारी है। कितना कर पाएगी यह तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन दिल्ली में वापस खड़ी हो गई यह अभी से दिखने लगा है। यहीं से कांग्रेस को कोई बड़ा नीतिगत फैसला लेना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है कि कांग्रेस ही भाजपा से लड़ रही है। मगर यथार्थ में होता यह है कि कई बड़े राज्यों में कांग्रेस दूसरे विपक्षी दलों के मुकाबले बहुत कमजोर हो जाती है। यूपी, बिहार, दिल्ली का तो अभी बताया ही मगर जम्मू-कश्मीर, झारखण्ड, पंजाब, महाराष्ट्र के अलावा दक्षिण और नार्थ ईस्ट के राज्यों में भी यही हालत हो गई है। कांग्रेस तीसरे-चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। यह तब है जब उसके पास इस समय देश का सबसे निर्दर, मेहनती और आम जनता से सबसे ज्यादा मिलने जुलने वाला नेता है। सच तो यह है कि कई बार यह कहा जाता है कि देश के लोग राहुल को नहीं पहचान पा रहे। सही बात है। चमक-दमक के इस झालर, पनी के दौर में असली मेटल को लोग नहीं पहचान पा रहे। मगर लोगों से शिकायत तो तब बनती है जब खुद उनकी पार्टी उहें सही से पहचान लेती। मुख्य बात तो यही है कि खुद कांग्रेस के नेता राहुल को नहीं पहचान पाए। उनके लिए राहुल भी एक चेहरा तो हैं मगर यह नहीं समझ पाए कि एक ऐसा शास्त्र उनके पास है जो कभी भी बाजी पलट सकता है। उनको सत्ता में ला सकता है। मुकाबला बहुत मुश्किल है। मोदी ने देश में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जनता पर किसी बात का असर नहीं हो रहा है। अभी कुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों की खबर चुप्पाई गई। अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट से पहले कुंभ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने की मांग करते हुए कहा कि हमें बजट के आंकड़े नहीं लापता लोगों के आंकड़े चाहिए। कितने लोग मारे गए। कितने घायल हैं और कितनों का पता नहीं है। विपक्षी दलों ने लोकसभा में जोरदार मांग उठाई, वाक आउट तक कर गए मगर सरकार निश्चिंत बनी रही। उसे लगता है विपक्ष आवाज उतारा रहे जनता नहीं सुनेगी। जनता को नफरत के ऐसे नशे में डाल दिया है कि वह कुछ भी नहीं सुनती, सोचती। बस उसे नफरती बातों से ही खुशी मिलती रहती है। कोई भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए जनता का नशा टूटता नहीं है। नोटबंदी, किसानों का आंदोलन बिना इलाज लोगों का मरांडा इंतजाम नहीं, पुलों से फेंकना, लॉकडाउन, लाखों जाना, चीन द्वारा धुस कर हात मारना, फिर वापस न जाना। इस बात को भी नकार देना धुसा है न कोई है, मगर किसी नहीं होना। ऐसे में राहुल का लगातार लड़ते रहना ही एक किरण रही। यहीं यह सवाल बढ़ावा देता है कि कांग्रेसियों को यह नहीं अपनी आदत से मजबूर हैं। वे करना है करें मगर हार गुटबाजी, काम न करना, लिस रहना में लगे रहेंगे। यह सिर्फ राहुल के खिलाफ है। 2019 में उन्होंने से अध्यक्ष दिलवाया गया था। राजस्थान गुटबाजी की बजह से हार गई हरियाणा भी ऐसे ही हार गयी था। लोग बड़े प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इसी क्रम में खड़ा करने वाले राज्यों में कारण अलग हरियाणा जो कि वह जैसी जाति तो क्या महाराष्ट्र के कांग्रेस हरियाणा जीत जाएगा?

न, कोविड चित्ता तक व शों का नी लजूरों का पैद र आदमियों व प्रधानमंत्री व कहना न के बात का अस जना हिम्मत ह मात्र आशा व ददा होता है विष खट्टखट्ट? या व ४ राहुल को उपने स्वार्थों २३ सिर्फ अंगनया गया थ दद से इस्ती नुबाह पूरी त था। और फि अगर इ अगर काग्रे रही थी जी नतीजे आते तो देश व

क्या डॉलर के दम पर चीन जैसे भरमासुर से निबटेगा अमेरिका?

कमलेश

बता दे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ने चतावनी दी है कि अगर ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह किसी और मुद्रा के इस्तेमाल का प्रयास करेंगे तो वह उन पर 100 प्रतिशत शुल्क लगा देंगे। चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है और ऐसा वह उस अमेरिका की कीमत पर करना चाहता है जिसने उसके नवनिर्माण और समुद्रात्मा में महती भूमिका निभाई है। हालांकि अमेरिका भी इसे भलीभांति समझ चुका है और समुपस्थित विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के डॉलर की चिंता और उसके लिए जिम्मेदार चीन सम्बन्धी हालिया बयानों पर जब आप गौर करेंगे तो यह समझ जाएंगे कि अमेरिका की चिंता सिर्फ डॉलर की गिरती साख को ही बचाने की नहीं है बल्कि वह सोवियत संघ की भाँति ही अब चीन को भी निबटाने की रणनीति पर फोकस कर चुका है। ऐसे में सुलगता सवाल यह है कि क्या अमेरिका सिर्फ डॉलर के दम पर चीन जैसे भस्मासुर से निबटेगा या फिर कुछ अन्य मौजूद उपाय भी करेगा! उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह किसी और मुद्रा के इस्तेमाल की कवायद जिस तरह से चीन कर-करवा रहा है और इस नजरिए से ब्रिक्स देशों यानी रूस-ब्राजील आदि को ढाल बनाए हुए हैं, उससे अमेरिका भड़क चुका है और सम्बन्धित देशों को खुलेआम धरमकियां देनी भी शुरू कर दी हैं। चीन के खिलाफ ताइवान का हथकंडा और दक्षिण चीन सागर विवाद को शह देने और रूस के खिलाफ युक्तेन को भड़काते रहने और नाटो देशों से सहयोग दिलवाने के पीछे की व्यापक रणनीति भी तो इसी बात की चुगली करती है। वहाँ, ब्रिक्स देशों की सम्भावित वैकल्पिक मुद्रा से डॉलर के समक्ष उत्पन्न होने वालों खतरों के सम्भावित दुष्परिणामों के बारे में अमेरिका ने जिस तरह से आगाह करना शुरू कर दिया है, उससे भारत समेत कतिपय ब्रिक्स देश भी सकते हैं, आशकित हैं और अपने बचाव में तर्क भी दे चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में जब ब्रिक्स के कुछ सदस्य देश विशेष रूप से चीन-रूस अमेरिकी डॉलर का विकल्प या ब्रिक्स मुद्रा की मांग कर रहे हैं, तब भारत %डी-डॉलराइजेशन% यानी %विश्व व्यापार और वित्तीय लेनदेन में डॉलर के उपयोग में कमी% के खिलाफ है। दिसम्बर 2024 में ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत कभी भी %डी-डॉलराइजेशन% के पक्ष में नहीं रहा है व ब्रिक्स मुद्रा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डॉक्टरों की बढ़ती आत्महत्याएँ : चिकित्सकों को चिकित्सा की जरूरत



है कि 40 प्रतिशत महिला डॉक्टर अत्यधिक तनाव में काम करती हैं। इस तनाव का सीधा संबंध मेंटल डिसऑर्डर और आत्महत्या के विचारों से है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री% में प्रकाशित एक शोध से भारत के डॉक्टरों के लिहाज से भी चिंताजनक तस्वीर उभरती है। इस जर्नल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत में 358 डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 70 प्रतिशत की उम्र मात्र 30 से 40 वर्ष के बीच थी। यह आंकड़ा केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। जब देश के युवा और प्रतिभाशाली डॉक्टर तनाव और मानसिक दबाव के कारण अपनी जान लेने पर मजबूर हो रहे हैं तो यकीनन यह हमारे हेल्थ केयर सिस्टम और समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। भारत के अध्ययनों से पता चलता है कि 40 प्रतिशत महिला डॉक्टरों को अत्यधिक तनाव की हालातों में काम करना पड़ रहा है। बढ़ता मानसिक असंतुलन और आत्महत्या के विचार इसके कारण हैं। डॉक्टर एमबीबीएस के बाद विशेषज्ञ बनने के लिए पीजी की तैयारी में जुट जाते हैं। एक तरफ काम का दबाव होता है, दूसरी ओर पढ़ाई की चिंता सताती है। इससे उपर्युक्त तनाव में संतुलन रखना बहुत कठिन होता है। शायद इसी का परिणाम है कि पिछले पांच सालों में 1270 मेडिकल छात्रों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इनमें 153 एमबीबीएस तथा 1117 पीजी में एडमिशन लेने वाले छात्र थे, जो क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा वजह से लोगों को इल शहरों की ओर भागना सरकार का दावा है कि जनसंख्या अनुपात % संगठन% (डब्ल्यूएचओ) निर्धारित मानदंडों से स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता भारत में %सामुदायिक (सीएचसी) में विशेषज्ञ कमी है। मंत्रालय द्वारा %स्वास्थ्य गतिशीलता और मानव संसाधन रिपोर्ट% के निकर्खों के क्षेत्रों में %सीएचसी% हजार 964 सर्जन,

की कमी के लिए बहुत अधिक संवेदनशील है। यह विषय प्रश्न स्वास्थ्य की ओर तरार है, मात्र लेते साल बढ़ते हैं। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य के दोनों टॉपिक्स पर भी ध्यान दिया जाएगा।

विशेषज्ञ, फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञों के मुकाबले भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 17 हजार 551 विशेषज्ञों की कमी है। सीनियर डॉक्टरों की मानें तो मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों पर अत्यधिक दबाव उनके लंबे और कठोर प्रशिक्षण, भारी कार्यभार, सामाजिक अपेक्षाओं और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी से उत्पन्न होता है। महिला डॉक्टरों को अपनी प्रोफेशनल लाइस के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी संतुलन बनाना पड़ता है, जिससे उनकी स्थिति और जटिल हो जाती है। अस्पतालों में तोड़फोड़, डॉक्टरों से मारपीट और अभद्र व्यवहार जैसी घटनाएं भी इस स्थिति के लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। वर्ष 2022 में राजस्थान के लालसोट में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत होने पर धरने-प्रदर्शन और पुलिस द्वारा अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से परेशान होकर सुसाइड कर लेने वाली युवा चिकित्सक डॉ. अर्चना शर्मा की मौत आज भी झकझोरती है। डॉ. अर्चना ने सुसाइड नोट में लिखा था कि %मैंने कोई गलती नहीं की है, किसी को नहीं मारा। प्रसवोत्तर रक्तस्राव (पीपीएच) एक कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए डॉक्टरों को प्रताडित करना बंद करो। % हाल में भरतपुर के रेडियोलोजिस्ट डॉ. राजकुमार चौधरी के आगरा में जाकर सुसाइड कर ली है। पूरे देश में इस तरह के मामले आते रहते हैं। यह समस्या बहुत बड़ी है जिसका त्वरित समाधान होना चाहिए, लेकिन यह तभी हो सकता है, जब समस्या की जड़ों तक पहुंचकर अस्तित्व की थाह ली जाए। यह जरूरी है कि महिला डॉक्टरों के दृष्टिगत %हेल्थ केयर सिस्टम% में लिंग संवेदनशील रणनीतियां प्रभावी ढंग से लागू की जाएं। कामकाजी माहौल को महिला डॉक्टरों के लिए अधिक अनुकूल बनाना होगा। इसके साथ ही, डॉक्टरों और छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

सरकार, मेडिकल संस्थानों, %इंडियन मेडिकल एसोसिएशन% और समाज को मिलकर ऐसे उपयोग करने होंगे, जिससे डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के लिए काम और जीवन के बीच संतुलन कायम करना आसान हो। यह भी आवश्यक है कि समाज की ओर से डॉक्टरों पर अनावश्यक अपेक्षाओं का बोझ न डाला जाए। डॉक्टर भी इंसान हैं, उनकी भावनाओं और सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर समाज के लिए जुटे रहते हैं, उसी प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग को भी डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य एवं सुकून को बनाए रखने के लिए योगदान देना चाहिए।

बात का बतांगड़ - तिल का ताड़ - राई का पहाड़

गोर्दिया - वैश्विक स्तरपर हजारों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति सभ्यता तथा बड़े बुजुर्गों की कहावतें और मुहावरों का पीढ़ियों से आज भी बहुत गुणगान नाम है। आज भी हम भारतवासियों को जो कि दुनियाँ के किसी भी कोने में बसे हो उसमें भारतीय संस्कृति सभ्यता का अंश किसी न किसी रूप में ज़रूर दिखेगा और किसी न किसी रूप से भारतीय मुहावरों का भी संज्ञान उनके जीवन में बसा हुआ है। चूंकि आज हम बड़े बुजुर्गों की कहावतों मुहावरों पर बात कर रहे हैं और और हम देख रहे हैं की 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा का चुनाव है जिसका रिजल्ट 8 फरवरी 2025 को आना है कि अनेक पार्टियों नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने स्तर पर समय का संज्ञान लेते हुए अनेक बातों को उछलकर बात का बतंगड़ बना दिया था किसी ने तिल का ताड़ तो किसी ने रई का पहाड़ बनाया था लेकिन हम जानते हैं कि यह सब चुनावी बातें हैं बातों का क्या? यह तो चुनावी बतंगड़ था? अब हम देखेंगे कि हर पार्टी नेता कार्यकर्ता ऐसी बातों का न बतंगड़ करेंगे और न ही ऐसे बयान देंगे और ना ही होगी। अब फिर 2025 के 2026 में कुछ राज्यों में विधान होने हैं, चुनावों में फिर हमें मुहावरों वाली बातें सुनाई ही आज हम मीडिया में उपलब्ध सहयोग से इस आर्टिकल के चर्चा करें, बात का बतंगड़ वाला और रई का पहाड़ (बीटीआर) साथियों वाला अगर हम बीटीआर की कर्ते तो बहुत छोटे को बहुत बड़ी बहस आरोप मुद्दा बना देने से है जैसा विधान अधी 5 फरवरी 2025 को होने विधानसभा चुनाव के चुनावी नेता कार्यकर्ता चुनाव में एक छोटी बातों को बीटीआर, अपनी बात को लेकर बहस, युवाओं में क्रोध के कारण और प्रत्यारोपों में हम देखते हैं इतनी बड़ी नहीं रहती जितना खतरनाक उसे बनाया जाता है इसका परिणाम बहुत बड़े

की चर्चा
त तक व
भा चुनाव
शी उपरोक्त
। इसलिए
नकारी के
वाध्यम से
का ताढ़

कृत तीनों
छोटी बातों
यारोप का
मने अप्पी
बाले दिल्ली
में देखाकि
दूसरे की
पत्ती में
जकल के
स आरोपों
कि बात
नक और
अप्पी-कभी
नुर्म और

सामाजिक बुराई का रूप धारण कर लेता है,
जिसमें हत्या संबंध विच्छेदन दुश्मनी बढ़ाना
शरीरिक व मानसिक हनि होने जैसे अनेक
घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए हम सभी को
चाहिए कि उपरोक्त तीनों बीटीआर से बहुत
ही दूर रहकर सावधानीपूर्वक अपनी वाणी
का प्रयोग कर हानियों से बचकर अपने
आपको समाज को और राष्ट्र को समृद्ध
बनाने में योगदान देने की कोशिश करें।
साथियों बात अगर हम उपरोक्त बीटीआर
की शुरुआत की करें तो यह मूल बात या
विषय जब एक कान से दूसरे कानों तक
पहुँचती है तो उस ऋम में हर एक
बिचौलिया जैसे की व्यक्ति या संस्था अपने
- अपने फायदे के अनुसार मूल बात को
तोड़ता मड़ोड़ता रहता है, तब बातों का मूल
विषय, भाव, या अभिप्राय बदल जाता है
बात बतंगड़ बन जाती है। और ज्यादातर
इसका हमारे समाज पर कुप्रभाव ही देखने
को मिलता है। पर इस बढ़ा चढ़ा कर की
गयी बात यानि बतंगड़ को पकड़ता कौन है?
आप हम यानि की जनता हूँ फिर जल्दी-
जल्दी ट्वीट डिलीट करने का और ये किसी

त विचार हैं पार्टी के नहीं ये सभी चल पड़ता है। हमने इस तरह बार को कई बार देखे हैं जिसकरना जरूरी है। साथियों हमने ना ही होगा ये गीत सुनिए कहिए - बातें में प्यार तो जब मुझकी हम कहेंगे की बातें में कहिए अम भी ना बातें करने लगे। बातें बहुत होती हैं पर जब गौर लूल में वही एक लाइनर छोटी सी गीतीआर करके बायरल कर दिया गया तो उसकी गायत्री जो होती थी स्मार्टफोन की तरह टची गयी और इसको किसकी बात बुझ आपने बड़े चाव से कोई शायरी पिकर खिंचवाया बस एक बायरल गया। वैसे बतंगड़ का मजा तब ल जम जाये जैसे नवोदियों प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कौन बायरल के यार दोस्त और गमधारी थे तो किसी चाय की दुकान पर पायी और फिर बतंगड़ शुरू हो गया आमने सामने बैठने बोल

बातों को जानने का प्रयास करते हैं, जो वह जानना चाहते हैं। और इसके भी दो कारण हो सकते हैं, या तो वह यह नहीं बताना चाहते कि वह क्या जानना चाहते हैं, या फिर वह कुछ हमसे कुछ छुपाना चाहते हैं। और सत्य तो यह है कि आज के समय में कोई बात करते समय या हमको बिल्कुल अहसास तक नहीं होने देता कि वह हमसे क्या जानना चाहता है, और वह बातों ही बातों में बात के बतांगड़ का प्रेशर देकर सब जान लेता है, जो वह जानना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह सीधे-सीधे हमसे पूछेगा तो हम नहीं बताएंगे तो वह जानने के लिए बीटीआर करेगा? सीधे-सीधे जानने के लिए हमसे बातों को धुमा कर पूछेगा, और हम फिर उनकी बातों को सोचेंगे, कि वह हमसे ही बातें कर रहे हैं, और यह हमारे ही फायदे के लिए है। इसलिए हमें उन्हें अपना जवाब सीधे-सीधे ही दे देते हैं। जिसके कारण इसका फायदा उठते हैं, और हमारी मन की बातों को जान जाते हैं।

